गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 278 | दि. 07-02-2019 गुरुवार | वि.सं. 2075 | महासुद -०२ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

अलीगढ़ में ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को अमित शाह ने संबोधित किया

हमने सर्जिकल स्ट्राइक की क्योंकि देश में मौनी बाबा नहीं मोदी की सरकार है

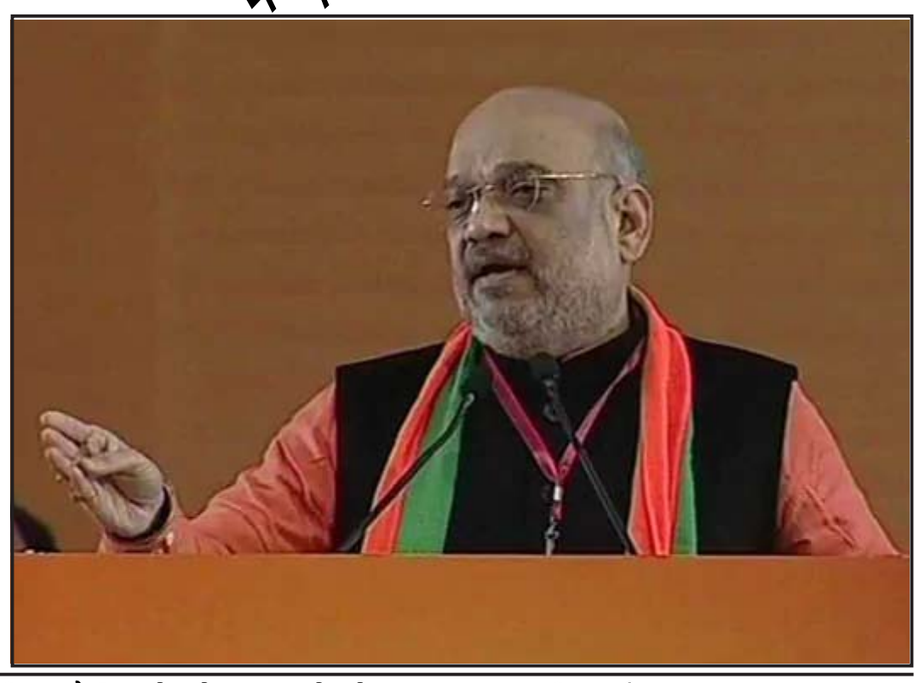

यूपीए की सरकार में घुसपैठिए देश में घुस आते थे : आलिया, मालिया जमालिया घुसते थे और धमाके करके भाग जाते थे : अध्यक्ष अमित शाह

(संपूर्ण समाचार सेवा) अलीगढ़,

अलीगढ़ में ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि उरी में बारह जवानों ने शहादत दी तो देश की सेना चुप नहीं बैठी। पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई क्योंकि देश में मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। इसके साथ ही शाह ने राम मंदिर मुद्दे पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। साथ ही शाह ने एसपी-बीएसपी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा, यूपीए की सरकार में घुसपैठिए देश में घुस आते थे। आलिया, मालिया जमालिया घुसते थे और धमाके करके भाग जाते थे। सरकार की कोई संजीदगी दिखाई नहीं पड़ती थी लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। शाह ने नागरिकता बिल का जिक्र करते हुए कहा, एनडीए की सरकार देश में नागरिकता बिल ला रही है ताकि घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए लेकिन विपक्षी पार्टियां एक हो गईं। ये घुसपैठिए इन पार्टियों के वोट बैंक है लेकिन बीजेपी के नहीं। अमित शाह ने रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोल रही है कि बीजेपी चाहती है कि अयोध्या में उसी स्थान पर राम मंदिर बने लेकिन बीएसपी, एसपी और कांग्रेस क्या चाहती हैं? ये पार्टियां राम मंदिर पर अपना मत स्पष्ट करें। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मौके पर उन्हें अलीगढ़ का ताला भेंट किया गया। अमित शाह ने कहा कि वह चाहते हैं बुआ-भतीजा की दुकान में यही अलीगढ़ का ताला लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि २०१७ में यूपी दंगों से त्रस्त था। आज दंगा करने वाले पलायन कर गए। गुंडे गले में लटकाकर घूम रहे हैं कि गिरफ्तार कर लो। पुलिस गुंडों से घबराती थी आज गुंडे पुलिस से घबरा रही है। शाह ने कहा कि राहुल गांधी आज किसानों और खेती की बात कर रहे हैं उन्हें तो यह भी पता नहीं कि कौन से फसल कब होती है? खरीफ की फसल क्या है कब होती? रबी की फसल कब होती है? खेत में आलू उगता है कि चिप्स उगता है? सीबीआई मुद्दे पर बंगाल में धरने पर बैठी ममता बनर्जी पर भी अमित शाह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल के अधिकारी से सीबीआई पूछताछ करना चाहती है तो इसमें ममता बनर्जी को क्यों बुरा लग रहा है? वह क्यों धरने पर बैठी हैं? उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि वह डरी हुई हैं कि अगर उस अधिकारी को जेल भेजा गया तो कहीं वह किसी का नाम न ले ले। अमित शाह ने कहा कि आखिर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अलीगढ़ में ब्रज क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को इशारों- इशारों में हिंदू विरोधी बताया है। भाषण के दौरान सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में पर्व और त्योहारों को शांति से मनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। एसपी और बीएसपी की सरकारों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा तक नहीं निकालने दी जाती थी। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई पर्व और त्योहार शांति पूर्ण तरीके से मनाया गया है। वेस्टर्न यूपी में कांवड़ यात्रा भी निकाली गई। यूपी सीएम ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार हर साल इस यूनिवर्सिटी को १५० करोड़ से ३०० करोड़ अनुदान देती है। लोगों के टैक्स से यह रुपया दिया जाता है। हर संस्थान में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों का आरक्षण मिलता है अलीगढ़ में क्यों नहीं दिया जाता है? सीएम ने कहा कि यहां भी आरक्षण लागू होना चाहिए। योगी ने कहा कि यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेस ने तुष्टिकरण के आधार पर लोगों को बांटा यही कारण है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू नहीं है।

तीन सैनिकों से मामले में पूछताछ की गई

सैनिक औरंगजेब के अपहरण और हत्या को लेकर पूछताछ

जानबूझ कर या अनजाने में औरंगजेब की गतिविधियों के बारे में सूचना लीक तो नहीं की गई इस बारे में पूछताछ

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर,

दक्षिण कश्मीर में पिछले साल आतंकवादियों द्वारा मारे गए सैनिक औरंगजेब की गतिविधि की सूचना देने में शामिल होने के संदेह में तीन सैनिकों से पूछताछ की जा रही है। सेना के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सेना के सूत्रों ने बताया कि तीन सैनिकों से पूछताछ इस संदेह को लेकर की जा रही है कि उन्होंने कही जानबूझ कर या अनजाने में औरंगजेब की गतिविधियों के बारे में सूचना लीक तो नहीं की। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन सैनिकों से पूछताछ की जा रही है उन्हें अब तक न तो हिरासत में लिया गया है, न हीं गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही हैं, वहीं सेना हर संभव सहयोग मुहैया करा रही है ताकि औरंगजेब की हत्या में शामिल लोगों को कानून के हवाले किया जा सके। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के घेरे में आए सैनिकों में से एक तौसीफ वानी का भाई है, जिसे शादीमार्ग शिविर में सेना के एक अधिकारी ने कथित तौर पर प्रताड़ित किया था। इसी शिविर में औरंगजेब की तैनाती थी। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही हैं, वहीं सेना हर संभव सहयोग मुहैया करा रही है ताकि

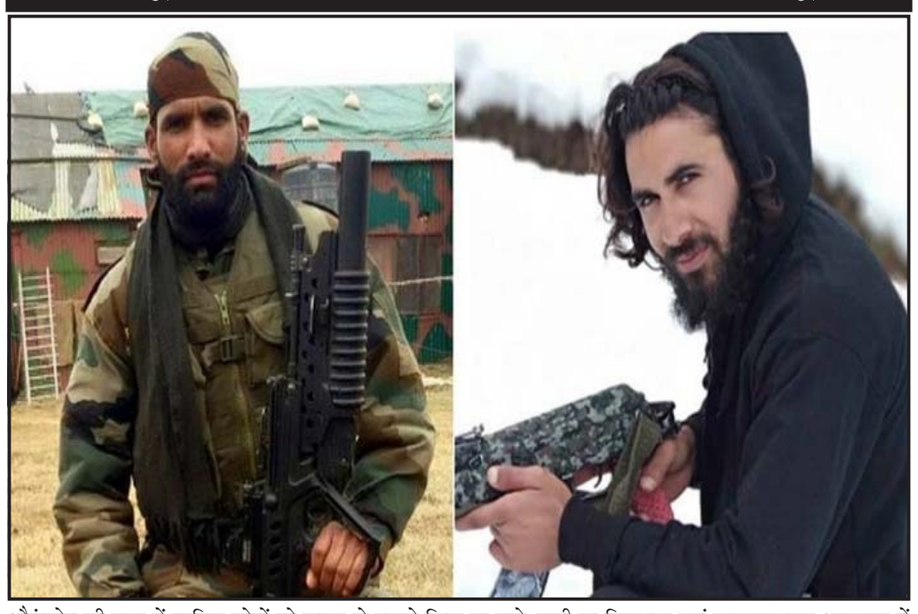

औरंगजेब की हत्या में शामिल लोगों को कानून के हवाले किया जा सके।वानी का फिलहाल यहां एमएमएचएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। ईद के मौके पर १४ जून २०१८ को छुट्टी पर जा रहे औरंगजेब को अगवा कर लिया गया था और बाद में सिर और गर्दन पर गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी।

अनशन में सिर्फ गांव-आसपास के लोग रहे साथ

२०११ का जलवा नहीं दोहरा पाए अन्ना हजारे

लोकपाल की नियुक्ति, राज्यों में लोकायुक्त कानून में बदलाव और किसानों को मांग को लेकर अनशन पर थे

(संपूर्ण समाचार सेवा) पुणे,

देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और जन लोकपाल विधेयक के लिए वर्ष २०११ में एक बुजुर्ग ने आंदोलन की शुरुआत की। देखते ही देखते पूरा देश उस बुजुर्ग के साथ जुड़ गया। लोगों के बीच यह बुजुर्ग अन्ना हजारे नए गांधी के रूप में उभरे और चंद दिनों के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी मुहिम का चेहरा बन गए। युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग, हर कोई अन्ना के साथ खड़ा था। जिस गांधी मैदान में अन्ना भूख हड़ताल पर बैठे, पूरा मैदान लोगों से पट गया। उन्हीं मांगों को लेकर अन्ना एक बार फिर आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन इस बार न तो वह भीड़ दिखी और न ही २०११ जैसा उत्साह दिखा। लोकपाल की नियुक्ति, राज्यों में लोकायुक्त कानून में बदलाव और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने की मांग को लेकर अन्ना अपने गांव रालेगण सिद्धि में पिछले सात दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे। उनकी हालत बिगड़ रही थी, जिससे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मनाने पर अन्ना मान गए और उन्होंने मंगलवार को अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। इस बार अन्ना हजारे को वह समर्थन नहीं मिला जैसा कि वर्ष २०११ में मिला था। अन्ना के आमरण अनशन में उनके गांव और आसपास के लोग ही साथ दिखे। जबकि वर्ष २०११ से वर्ष २०१४ तक आम जनता के साथ-साथ मुख्य विपक्ष बीजेपी भी अन्ना के साथ खड़ी दिखी थी। इस बार विपक्षी पार्टियां अन्ना हजारे से दूर दिखीं। यही

नहीं उनके समर्थन में भी विपक्ष की तरफ से कुछ खास आवाज नहीं उठा। हां, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जरूर महाराष्ट्र सरकार को अन्ना हजारे के जीवन के साथ ना खेलने की चेतावनी दी थी। जबकि वर्ष २०११ में अन्ना के सबसे करीबियों में से एक रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द भी इस उपवास के बारे में नहीं बोला।

आईएनएक्स मीडिया मामला

चिदंबरम को अतिरिक्त दस्तावेज लगाने की मंजूरी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता पी चिदंमबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा दायर मामले में अग्रिम जमानत के लिये लंबित उनकी याचिका में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जोड़ने की मंजुरी दे दी। पूर्व वित्त मंत्री ने तीन फरवरी को प्रकाशित कुछ समाचार लेखों के प्रिंट अदालत में पेश करने की मंजूरी मांगी थी जिनमें कहा गया है कि विधि मंत्रालय ने केंद्र को बताया है कि मामले में सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी जा सकती है। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने आवेदन को मंजूर करते हुए कहा कि अतिरिक्त दस्तावेजों को जमानत याचिका के साथ शामिल किया जाए।

कांग्रेस मुख्यालय पहुंचीं प्रियंका गांधी वाड्रा

प्रियंका ने पूर्वी यूपी के प्रभारी महासचिव का पदभार संभाला

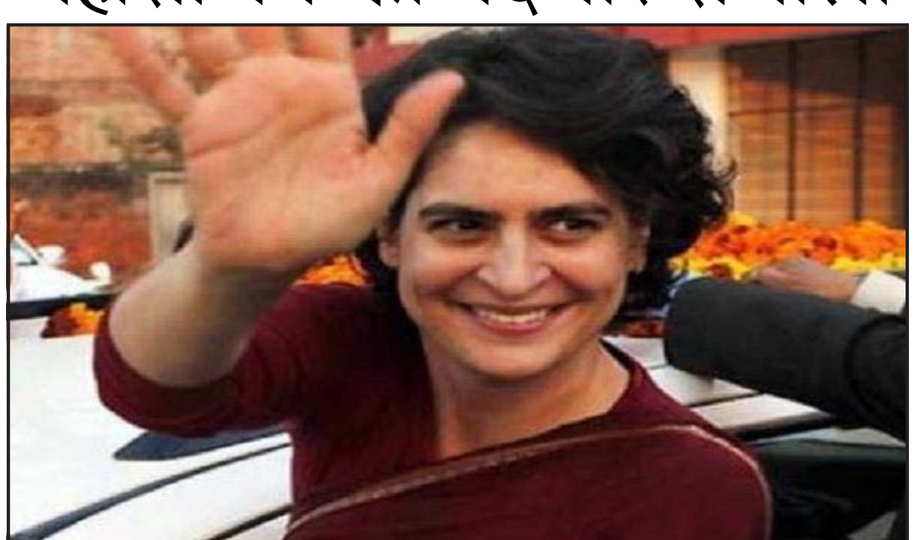

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर पदभार संभाला। उन्हें महासचिव-प्रभारी (पूर्वी उत्तर प्रदेश) नियुक्तकिया गया है। प्रियंका शाम करीब साढ़े चार बजे २४ अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचीं। उससे पहले वह अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर छोड़ने गईं, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिग केस के सिलसिले में पूछताछ हो रही है। अपने पति को ईडी दफ्तर छोड़ने के बाद प्रियंका वाड्रा सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचीं। उनके कांग्रेस मुख्यालय के पहुंचने के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए और प्रियंका गांधी जिंदाबाद और प्रियंका नहीं ये आंधी, दूसरी इंदिरा गांधी के नारे लगाने लगे। इससे पहले पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। हाल ही में प्रियंका को महासचिव-प्रभारी (पूर्वी उत्तर प्रदेश) और सिंधिया को महासचिव-प्रभारी (पश्चिमी उत्तर प्रदेश) नियुक्त किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस

सीबीआई विवाद पर ट्वीट कर फंस गए प्रशांत भूषण

ट्वीट में कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल ने जानबूझकर कोर्ट में पेंडिंग केस के बारे में गलत जानकारी दी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

बीते दिनों सीबीआई बनाम सीबीआई मामले पर टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण फंसते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में प्रशांत भूषण पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जानबूझकर कोर्ट में पेंडिंग केस के बारे में गलत जानकारी दी। इस मामले की अगली सुनवाई ७ मार्च को होगी। एक तरफ जहां अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल इस मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ सजा नहीं चाहते हैं, वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट की अवमानना के लिए प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एजी ने कोर्ट से कहा, मैं प्रशांत भूषण के आरोपों से आहत हूं। मैं प्रशांत भूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन कोर्ट को यह तय करना चाहिए कि पेंडिंग मामलों को लेकर किसी वकील को किस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए और क्या नहीं जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, हम कोर्ट की कार्रवाई की मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोर्ट में लंबित मामले से जुड़े एडवोकेट को मीडिया में बयान देने या टीवी डिबेट में भाग लेने से बचना चाहिए। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर कथित तौर पर कुछ विवादित ट्वीट के लिए प्रशांत भूषण पर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी। दरअसल भूषण ने पिछले दिनों कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बारे में केंद्र की दलील है कि वे एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति से जुड़े लंबित मामले में गलत बयान देने जैसे हैं। कुछ दिनों पहले अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने भी कथित ट्वीटों के लिए भूषण के खिलाफ ऐसी ही अवमानना की याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को एनजीओ कॉमन कॉज की उस याचिका पर सुनवाई करेगी।

संपादकिय

वांछित तत्वों पर जल्द नकेल कसने के लिए प्रत्यर्पण की लंबी प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए

भारत में घपला–घोटाला या अन्य कोई अवैध–अनुचित काम कर विदेश में छिपने वालों को स्वदेश लाने के लिए कूटनीतिक गतिविधियों को गति देना समय की मांग है, लेकिन इसी के साथ उन उपायों पर भी गौर किया जाना चाहिए जिससे प्रत्यर्पण में कम से कम समय लगे। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर मामलों में विदेश में जा छिपे लोगों को भारत लाने में कहीं अधिक समय लग जाता है। निस्संदेह यह राहतकारी है कि ब्रिटेन के गृह मंत्री ने विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी, लेकिन अभी यह तय नहीं कि वह भारत के हाथ कब लगेंगे। विजय माल्या ब्रिटेन के गृहमंत्री के आदेश के खिलाफ वहां के उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। यदि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को सही पाया तब जाकर उनका भारत आना सुनिश्चित हो सकेगा। हालांकि इसके आसार न के बराबर हैं कि उच्च न्यायालय निचली अदालत के आदेश में कोई हेरफेर करेगा, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपना फैसला कब सुनाएगा? देखना यह भी होगा कि ब्रिटिश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विजय माल्या भारत आने से बचने के लिए कोई जतन करते हैं या नहीं? ध्यान रहे कि वह भारत आने से बचने के लिए किस्म–किस्म के बहाने ग ?ते रहे हैं। यही काम पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी कर रहे हैं। जहां नीरव मोदी यह राग अलाप रहे कि उन्हें भारत में खलनायक की तरह देखा जा रहा वहीं मेहुल चोकसी यह बहाना पेश कर रहे कि वह एंटीगुआ से भारत तक का लंबा हवाई सफर नहीं कर सकते। विडंबना यह है कि कई बार इस तरह की बहानेबाजी को संबंधित देशों की अदालतें महत्व देने लगती हैं।

यह एक तथ्य है कि ब्रिटेन की अदालतों ने भारत में वांछित कई तत्वों को इस आधार पर प्रत्यर्पित करने से मना कर दिया कि यहां की जेलों की दशा अच्छी नहीं है। एक ओर जहां ब्रिटेन जैसे देश हैं, जहां का प्रत्यर्पण संबंधी तंत्र कुछ ज्यादा ही जटिल है वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं जो वांछित शख्स की पहचान स्थापित होने और उसकी कारगुजारी का विवरण मिलते ही उसे प्रत्यर्पित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी देश हैं जो प्रत्यर्पण के मामले में एक तरह से मनमाना रवैया प्रदर्शित करते हैं। पुरुलिया कांड में वांछित किम डेवी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए, क्योंकि वहां की सरकार भारत की चिंता समझने के बजाय अपने आपराधिक अतीत और छवि वाले नागरिक की हिफाजत को ज्यादा अहमियत दे रही है। यह सही है कि पुर्तगाल सरीखे यूरोपीय देश मानवाधिकारों को कहीं अधिक अहमियत देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे इसके नाम पर अपराधियों का बचाव करें। जरूरी केवल यह नहीं है कि पुर्तगाल सरीखे देशों के प्रति सख्त कूटनीति का परिचय दिया जाए, बल्कि यह भी है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज भी उठाई जाए ताकि ऐसा कोई कानून बन सके जिससे वांछित तत्व बहानेबाजी कर प्रत्यर्पण से बचने न पाएं।

सारधा–रोज वैली जैसे घोटालों की ऐसी जांच न हो जिसमें पीडितों को राहत न मिल सके

(जी.एन.एस.) हजारों करोड रुपये के चिटफंड घोटालों की सीबीआइ जांच को लेकर ममता और मोदी सरकार के बीच छि? घमासान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्ष जो मन में आए वह दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता कि उन लाखों लोगों के मन में उम्मीद की कोई किरण जगी होगी जिन्हें सारधा और रोज वैली नामक चिटफंड कंपनियों ने लूटा। एक आंकडे के अनुसार इन दोनों चिटफंड कंपनियों ने करीब 22 लाख लोगों के लगभग 20 हजार करोड रुपये की लूट इसलिए आसानी से कर सकीं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीडिया के भी कई लोगों को अपने धनबल से संतुष्ट रखा। सारधा घोटाला 2013 में ही सतह पर आ गया था। ममता सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल के प्रमुख वही राजीव कुमार थे जो इस समय कोलकाता के पुलिस आयुक्त हैं और जिनसे सीबीआइ की पूछताछ को लेकर कोहराम मचा। जब विशेष जांच दल से जांच को नाकाफी बताकर सीबीआइ जांच की मांग हुई तो ममता सरकार ने ऐसी किसी जांच का विरोध किया, रुपये हये दोनों कंपनियां हजारों करोड रुपये की लूट इसलिए आसानी से कर सकीं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीडिया के भी कई लोगों को अपने धनबल से संतुष्ट रखा। सारधा घोटाला 2013 में ही सतह पर आ गया था। ममता सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल के प्रमुख वही राजीव कुमार थे जो इस समय कोलकाता के पुलिस आयुक्त हैं और जिनसे सीबीआइ की पूछताछ को लेकर कोहराम मचा। जब विशेष जांच दल से जांच को नाकाफी बताकर सीबीआइ जांच की मांग हुई तो ममता सरकार ने ऐसी किसी जांच का विरोध किया, प फिए। इन दिनों भले ही सारधा घोटाले की जांच को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ हो, लेकिन इस घोटाले से बडा घोटाला रोज वैली कंपनी ने अंजाम दिया था। ये दोनों कंपनियां हजारों करोड रुपये की लूट इसलिए आसानी से कर सकीं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीडिया के भी कई लोगों को अपने धनबल से संतुष्ट रखा। सारधा घोटाला 2013 में ही सतह पर आ गया था। ममता सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल के प्रमुख वही राजीव कुमार थे जो इस समय कोलकाता के पुलिस आयुक्त हैं और जिनसे सीबीआइ की पूछताछ को लेकर कोहराम मचा। जब विशेष जांच दल से जांच को नाकाफी बताकर सीबीआइ जांच की मांग हुई तो ममता सरकार ने ऐसी किसी जांच का विरोध किया, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए सीबीआइ जांच के आदेश दिए कि इस घोटाले का दायरा पश्चिम बंगाल के बाहर पये दोनों कंपनियां हजारों करोड रुपये की लूट इसलिए आसानी से कर सकीं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीडिया के भी कई लोगों को अपने धनबल से संतुष्ट रखा। सारधा घोटाला 2013 में ही सतह पर आ गया था। ममता सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल के प्रमुख वही राजीव कुमार थे जो इस समय कोलकाता के पुलिस आयुक्त हैं और जिनसे सीबीआइ की पूछताछ को लेकर कोहराम मचा। जब विशेष जांच दल से इस जांच को नाकाफी बताकर सीबीआइ जांच की मांग हुई तो ममता सरकार ने ऐसी किसी जांच का विरोध किया, तो राज्यों में भी फैला हुआ है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारधा के साथ अन्य चिटफंड कंपनियों की भी जांच जरूरी बताई इसलिए रोज वैली कंपनी भी सीबीआइ जांच के दायरे में आई। जल्द ही यह पता चला कि रोज वैली कंपनी ने तो कहीं अधिक लोगों को ठगा है। यह सही है कि बीते चार सालों में सारधा और रोज वैली घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कई लोग जेल भी गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इन दोनों घोटालों की जांच कब तक जारी रहेगी? इस बारे में तो दूर–दर तक कोई खबर ही नहीं कि इन दोनों कंपनियों की ठगी का शिकार हुए लाखों लोगों को किसी तरह की कोई राहत कब मिलेगी? हालांकि सारधा और रोज वैली कंपनियों के संचालकों की तमाम संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन कंपनियों की संपत्तियां बेचकर ठगी के शिकार हुए लोगों को राहत देने की कोई कोशिश होती नहीं दिख रही है। इस तरह के घोटालों की वैसी जांच का कोई मतलब नहीं जिसमें पीडित लोगों को राहत मिलने की कोई सूरत न नजर आए। हो सकता है कि सीबीआइ जांच सही दिशा में हो, लेकिन क्या इसकी अनदेखी कर दी जाए कि वह अभी तक वे दस्तावेज भी हासिल नहीं कर सकी है जो राजीव कुमार ने विशेष जांच दल के प्रमुख के नाते सारधा कंपनी के मुखिया सुदीप्त सेन और उसकी सहयोगी देवजानी मुखर्जी से हासिल किए थे। सीबीआइ की मानें तो देवजानी ने यह खुलासा किया था कि विशेष जांच दल ने उसके पास से एक लाल डायरी और पेन ड्राइव समेत कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। यह हैरानी की बात है कि सीबीआइ अभी तक वह लाल डायरी और पेन ड्राइव की ही तलाश कर रही है। माना जाता है कि इसी लाल डायरी और पेन ड्राइव के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सीबीआइ कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करना चाह रही थी। ये दोनों कंपनियां हजारों करोड रुपये की लूट इसलिए आसानी से कर सकीं, क्योंकि उन्होंने तमाम नेताओं के साथ मीडिया के भी कई लोगों को अपने धनबल से संतुष्ट रखा। सारधा घोटाला 2013 में ही सतह पर आ गया था। ममता सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। इस जांच दल के प्रमुख वही राजीव कुमार थे।

गरीबों को एक रुपये में चावल और कन्या विवाह के लिए एक तोला सोना देगी असम सरकार

(जी.एन.एस.) गुवाहाटी, असम सरकार ने बजट में गरीबों के लिए एक रुपये किलो चावल और कन्या विवाह के लिए एक तोला सोना देने की व्यवस्था की है। सरकार ने कोई नया कर भी नहीं लगाया है। विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तुत बजट में कुल 1,799.84 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान है। राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने बताया, हम एक रुपये प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराएंगे। इसका लाभ राज्य के 53 लाख परिवारों को मिलेगा। शादी योग्य गरीब युवतियों के परिजनों को एक तोला (11.66 ग्राम) सोना देने का भी प्रावधान है। अरुंधति योजना के तहत इसका लाभ सभी वर्ग के गरीबों को मिलेगा। इस वर्ग में वे लोग आएंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय पांच लाख रुपये से कम है। परिवार की पहली दो संतानों को दिए जाने वाले इस तोहफे के लिए सरकार ने अलग से 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। राज्य में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक फरवरी से जीएसटी का दायरा बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। सरकार ने छात्रों के लिए हॉस्टल फीस माफ करने के साथ–साथ विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन की भी घोषणा की है। अब 12वीं की बजाय स्नातक तक मुफ्त किताबें दी जाएंगी। उच्च माध्यमिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाली सभी छात्राओं को ई–बाइक दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए वजीफे का भी प्रावधान किया गया है। जिन परिवारों की आय दो लाख रुपये सालाना से कम होगी, उनके बच्चों को कॉलेज में मुफ्त दाखिला मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए लोन लेने वालों को सरकार एकमुश्त 50 हजार रुपये देगी। सरकार ने भारतीय मूल के अल्पसंख्यकों के लिए विकास निगम के गठन की घोषणा भी की है। चाय बागान के श्रमिकों को मुफ्त चावल व दो किलो चीनी देने का एलान किया गया है। 45 साल से कम उम्र की विधवाओं को 25 हजार रुपये की मदद दी जाएगी।

विवादित होर्डिंग्स हटाना एएमसी लिए अनिवाय

आसाराम के फोटो के साथ पोस्टर का नया विवाद हुआ

कुछ दिन पहले भूपेन्द्रसिंह चुडासमा ने आसाराम की संस्था को शुभकामना का पत्र लिखा तब विवाद पैदा हो गया

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, कुछ दिन पहले भाजपा के नेता भूपेन्द्रसिंह चुडासमा ने आसाराम की संस्था को शुभकामना का पत्र लिखा तब उनको कई जवाब देने की परिस्थिति आ गई थी क्योंकि उनके पत्र से गंभीर विवाद पैदा हो गया। यह विवाद अभी शांत हो उसके पहले शहर में आसाराम की फोटो के साथ कई क्षेत्रों में लगे विशाल होर्डिंग्स का एक नया विवाद सामने आया। एएमटीएस बस स्टेंड पर कॉर्पोरेशन ने आसाराम के पोस्टर्स लगाने से भारी विवाद पैदा हो गया। आगामी १४ फरवरी को वेलेन्टाइन डे के दिन मां–फादर्स डे मनाने के लिए आसाराम ट्रस्ट द्वारा पोस्टर्स लगाया गया, जिसे लेकर एएमसी प्रशासन के विरूद्ध शहरीजनों में भारी नाराजगी फैल गई। आसाराम के फोटो के साथ होर्डिंग्स को लेकर एएमसी प्रशासन के विरूद्ध लोगों द्वारा सवाल उठाये जाने से आखिर में कॉर्पोरेशन शासकों को यह होर्डिंग्स तुरंत हटा लेने की सूचना दी गई है। हालांकि, लोगों में और शहर के जागरूक नागरिकों में ऐसे गंभीर सवाल एएमसी प्रशासन से पूछे जा रहे है कि, ऐसे बलात्कार सहित के गंभीर केस में शामिल रहे आसाराम की फोटो के साथ होर्डिंग्स लगाने से पहले एएमसी प्रशासन ने मंजूरी किस तरीके से दी क्या उनको अहमदाबाद शहर की संस्कृति और प्रतिष्ठा की जानकारी नहीं है। ऐसे तत्वों की फोटो के साथ होर्डिंग्स के द्वारा एएमसी शासक समाज को विशेष करके बच्चों और युवाओं को क्या संदेश देने चाहते हैं ऐसे गंभीर सवाल उठाने से एएमसी शासक बेकफुट पर आ गये और यह विवादित होर्डिंग्स हटा लेने की सूचना दी गई। आगामी १४ फरवरी को वेलेन्टाइन डे है। यह दिन में आसाराम आश्रम की संस्था योग वेदांत सेवा समिति ने मां–फादर्स पूजा दिवस के तौर पर मनाया जाए ऐसा पोस्टर तैयार किया गया और अहमदाबाद में जगह–जगह पोस्टर्स लगाने जाने से कई लोग बलात्कारी बाबा के नाम के पोस्टर्स देखकर नाराज हो गये थे। पोस्टर्स भी सोशल मीडिया में वायरल हो जाने से भारी नाराजगी देखने को मिली थी।

रिव्यू- स्टाइल, सेफ्टी और कीमत में कैसा रहेगा यह हेल्मेट

नई दिल्ली (श्रीधर मिश्रा)। आज हमारे पास Steelbird ·Ô- Air रेंज का एक बेहद ही खास और नया मॉडल SBA-6 है। हम आपको इस हेल्मेट से जुड़ी हर छोटी–बड़ी बातों के बारे में बताएंगे। इसके साथ यह भी जानेंगे कि क्या यह हेल्मेट आपके लिए एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है? Steelbird SBA-6 को अच्छे से समझने के लिए इस हेल्मेट को कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। SBA-6 एक ओपेन–फेस हेल्मेट है। ओपेन–फेस हेल्मेट को आसान भाषा में समझे तो इसमें सामने की तरफ आपको केवल 1isor(ग्लास) मिलता है। यानी की जबड़े को बचाने के लिए इसमें अलग से कवर या प्रोटेक्शन नहीं मिलता है।SBA-{, Steelbird ·Ô¤ Air रेंज का सबसे नया मॉडल है। यह श्वघ्ड्ड और स्नह्व5द्र नाम के दो वेरिएंट

में आता है। श्वघ्ड्ड वेरिएंट महिलाओं के लिए है और Fuze वेरिएंट मर्दों के लिए। इन दोनों वेरिएंट के इंटीरियर को देखने के बाद आप आसानी से इनमें अंतर कर सकते हैं। आज हम जिस हेल्मेट का रिव्यू कर रहे हैं वो स्नह्व5द्र वेरिएंट है।SBA- के Fuze वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,239 रुपये है। वहीं, Ela वेरिएंट की शुरुआती कीमत 1,289 रुपये है।SBA-6 हेल्मेट Steelbird कंपनी के Air रेंज का सबसे किफायती मॉडल है। आपको बता दें कि द्बह्न रेंज की कीमत 3,409 रुपये तक जाती है। अगर इस हेल्मेट की सबसे बड़ी खासियत के बारे में पूछा जाए,

ठग गिरोह कॉल के तहत लोगों को जाल में फंसाते

लोगों को धोखा देती गैंग के ९ शख्सों की गिरफ्तारी

आश्रम रोड पर स्थित वासुकानन अपार्टमेंट में चलता फर्जी कॉल सेंटर की साइबर क्राइम द्वारा पर्दाफाश किया

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, विदेश में लोन देने के बहाने या फिर, बैंक के अधिकारी बनकर लोगों के पास से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीन नंबर और ओटीपी नंबर लेकर लाखों का बाहर ही ट्रांसफर करने के कॉल सेंटर चल रहे हैं। अब शेयरबाजार में निवेश कराने की लालच देकर ठगाई करते कॉल सेंटर का पर्दाफाश साइबर क्राइम ने करके नौ शख्सों की गिरफ्तारी की गई है। ठग गिरोह ने अब शोर्टकट से रुपया कमाने के लिए जगह–जगह छोटे–बड़े कॉल सेंटर शुरू करके शेयरबाजार में निवेश के नाम पर लोगों को फंसाना शुरू किया गया। लेकिन साइबर क्राइम में मिली शिकायत की वजह से चुनिंदा अधिकारियों की टीम ने यह पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया गया और नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में साइबर क्राइम के पुलिस इंस्पेक्टर वीबी. बारड के बताये अनुसार, यह पूरे घोटाले मामले में एक व्यक्ति ने नौ लाख की धोखाधड़ी की शिकायत साइबर क्राइम में दर्ज कराई थी। शेयरबाजार में निवेश करने का बताकर शिकार होने वाले व्यक्ति को चोरों ने विश्वास में ले लिया था। कुछ दिनों तक शेयरबाजार की अलग–अलग लुभावनी स्कीम बताकर शिकार होने वाले को विश्वास में लिया गया। शिकार बनने वाले को विश्वास हो जाने पर उसने चोर के खाते में नौ लाख रुपये ट्रांसफर कर दिया था। नौ लाख रुपये ट्रांसफर होने के साथ ही चोर ने अपना मोबाइल फोन स्वीच ऑफ कर दिया था। इस मामले में साइबर क्राइम ने अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच करने पर साइबर क्राइम के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि आश्रम रोड पर स्थित वासुकानन अपार्टमेंट में एक फर्जी कॉल सेंटर चल रतहा है। मिली जानकारी के आधार पर साइबर क्राइम के पुलिस कर्मचारियों ने छापेमारी की गई। जिसमें नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर चला रहे मुख्य सूत्रधार की पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया था कि, लोगों के पास से शेयरबाजार में निवेश के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे।

असल मुद्दों के अभाव से जूझती कांग्रेस, प्रियंका को जन कल्याणकारी मुद्दों का प्रतीक बनना होगा

(जी.एन.एस.) वर्ष 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था कि 'अब हर सुबह अखबारों में एक सुंदर चेहरा देखने को मिलेगा।' कांग्रेस इससे खुश थी कि एक महान पिता की पुत्री होने का उसे चुनावी लाभ मिल जाएगा। चीन के हाथों अपमानजनक पराजय और अन्य कई कारणों से कांग्रेस और उसकी सरकार पस्त थी। सरकार के प्रति असंतोष बड रहा था। जहां–तहां जन आंदोलन हो रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। यानी मुश्किल वक्त में कांग्रेस को एक नया चेहरा मिल गया। हालांकि शुरुआत में इंदिरा गांधी चुनाव में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाईं। कांग्रेस ने 1967 के चुनावी घोषणा पत्र में समृद्धि लाने का वादा किया। गरीब देश के लिए यह ब ?ा वादा था। चूंकि ऐसी किसी सरकारी पहल का इंदिरा गांधी सरकार का कोई इतिहास नहीं था इसलिए लोगों ने सिर्फ वचन पर भरोसा नहीं किया। जो लोग न्यूनतम आय गारंटी के राहुल गांधी के वायदे से उत्साहित हैं उन्हें 1967 का चुनावी इतिहास याद कर लेना चाहिए। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की 283 सीटें मिलीं जबकि 1962 में उसे 361 सीटें मिली थीं। ऐसा तब हुआ जबकि इस दौरान लोकसभा सीटों की संख्या ब ? गई थी। यही नहीं, देश के सात राज्यों में भी कांग्रेस चुनाव हार गई। स्मरण रहे कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ होते थे। वर्ष 1967 के आम चुनाव के कुछ ही महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेसियों के दल–बदल के कारण पार्टी की चुनी हुई सरकारें भी गिर गईं। इससे उत्तर प्रदेश में चरण सिंह और मध्य प्रदेश में गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने। ऐसे में 1967 से सबक लेकर 1969 में जब इंदिरा गांधी ने जन कल्याणकारी मुद्दों से पार्टी और खुद की सरकार को जो ?ा तो उन्हें 1971 के चुनाव में भारी सफलता मिली। 1971 में कांग्रेस को लोकसभा की 352 सीटें मिलीं। इसका पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को गया। उनके 'गरीबी हटाओ' के नारे को बडी संख्या में लोगों ने पसंद किया। जो लोग सिर्फ चेहरे के आधार पर प्रियंका गांधी से कुछ उम्मीद कर रहे हैं वे इंदिरा गांधी के इस इतिहास को भी जान लें तो बेहतर। 1969 में कांग्रेस में महा विभाजन हुआ था। कांग्रेस संगठन से जडे लगभग सारे बडे नेता मूल कांग्रेस में रह गए। इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस(आई) बना ली। इसके बाद उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे को पूरा करने के मकसद से 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राजा–महाराजाओं को मिलने वाले प्रिवीपर्स भी खत्म कर दिए। गरीबों को लगा कि इंदिरा गांधी हमारी गरीबी हटाने के लिए ही अमीरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। जनता को बाद में भले धोखा मिला हो, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद को जन कल्याणकारी मुद्दों से जोडलिया था। वह उनका प्रतीक बन गई थीं। आगामी चुनाव में प्रियंका गांधी को बताना होगा कि वह और उनकी पार्टी कौन से जन कल्याणकारी मुद्दों की प्रतीक हैं। यदि वह ऐसा कुछ साबित कर सकीं तभी बात बनेगी, अन्यथा वही हश्र होगा जो 1977 के चुनाव में हुआ था। तब आपातकाल के बाद हुए आम चुनाव में सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। तब लोगों के जेहन में बस आपातकाल की ज्यादतियां थीं। लोगों को यह भी कुपित कर रहा था कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाली इंदिरा गांधी कैसे अपने बेटे संजय गांधी के लिए मारुति कार का कारखाना लगवाने में जुटी हैं।

कांग्रेस सरकार ने 2004 से 2014 तक जो किया उसका नतीजा उसे 2014 में मिल चुका है। उसके बाद कांग्रेस की चर्चा इस बात के लिए अधिक हो रही है कि उसके कितने नेताओं के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। कितने नेता जमानत पर हैं। इसी क्रम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मामलों की भी चर्चा है। कांग्रेस के पास नया कुछ भी नहीं है। हालांकि इंदिरा गांधी को 1969 में नया मुद्दा पकडने में समय नहीं लगा था, क्योंकि उनके पास पहल करने के लिए अपनी सरकार थी। वहीं 1977 में गठित मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने भी इंदिरा गांधी को मौका तश्तरी में पेश करके दे दिया। जब सत्तारू ? जनता पार्टी के तीन शीर्ष नेता आपस में लडने लगे और देश में राजनीतिक अस्थिरता की नौबत आ गई तो लोगों ने एक बार फिर इंदिरा गांधी को याद किया। इंदिरा गांधी 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आ गईं तो उनके पास राजनीतिक स्थिरता का नारा था। यह तब बडा मुद्दा बन गया था। आज कांग्रेस के पास कौन सा लोकलुभावन मुद्दा है? हां, विभिन्न गैर राजग दलों से गठजोड का रास्ता जरूर है। उसके लिए वह प्रयासरत है। लगता है कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व को मुद्दे गडना भी नहीं आता। हालांकि उससे जुडने का सुबूत जनता को तब मिलेगा जब सत्ता में रहकर उस दिशा में कोई जन कल्याणकारी निर्णय किया जाए।

जवाहरलाल नेहरू तो आजादी की लडाई के नायक थे। उनके बारे में लोगों में यह धारणा थी कि सुखमय जीवन छोडकर उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था। स्वतंत्रता सेनानियों के पुण्य प्रताप से कांग्रेस को आजादी के बाद के तीन–चार चुनावों में कोई दिक्कत नहीं हुई। मगर जब भ्रष्टाचार बडा और साथ ही लोगों की समस्याएं भी तो कांग्रेस सरकारों की कठिनाइयां बडने लगीं। आज तमाम कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में चल रहे मुकदमों की चर्चा है। ऐसे में प्रियंका कैसे करिश्मा दिखा पाएंगी? करिश्मा दिखाने का ऐसा अवसर राजीव गांधी को जरूर मिला था। 2004 से 2014 तक जब करिश्मा दिखाने अवसर मिला था तब कांग्रेस के अधिकांश शीर्ष नेता दूसरे ही कामों में लगे थे।

सारा के पास काफी फिल्मो के ऑफर आ रहे हैं

सारा अली खान ने रिजेक्ट की टाइगर के संग बागी ३

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अब तक केदारनाथ और सिंबा में नजर आई हैं। इन दो फिल्मों के बाद से ही उनके पास तमाम फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। खबर है कि सारा को टाइगर श्रॉफ के अपोजिट फिल्म बागी ३ के लिए भी अप्रोच किया था, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सारा ने बागी ३ में काम करने से इनकार कर दिया है। सिंबा ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की हो, लेकिन रणवीर सिंह के मुकाबले फिल्म में सारा का रोल बेहद छोटा रोल था। सिंबा में सारा अली खान मुश्किल से १५ मिनट ही नजर आई थी और इसके अलावा उनके खाते में आंख मारे जैसा फेमस गाना आया था, ऐसे अगर बागी ३ में भी उनका किरदार फिल्म के हीरो टाइगर श्रॉफ की तुलना में छोटा होता तो उनके फिल्मी करियर पर सवाल खड़े होते है। शायद यही वजह है कि सारा ने 'बागी ३' में काम करने से साफ मना कर दिया। अपनी शुरुआती २ फिल्मों के बाद सारा इन दिनों अपनी अगली फिल्मों, कहानियों का चुनाव बेहद सावधानी से कर रही हैं। सारा परदे पर दमदार किरदार के साथ आना चाहती हैं। शुरुआती समय में कमजोर और छोटे रोल करना वह करियर के लिए ठीक नहीं समझती हैं। इतनी कड़ी प्रतियोगिता के बीच लंबे और दमदार रोल के बाद ही वह दर्शकों के बीच अपनी जगह बना पाएंगी। सारा ने अपने करियर की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म केदारनाथ से की थी। केदारनाथ भले ही कमाई के मामले में पिछड़ गई थी, लेकिन सारा सारा ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया था। बाद में सारा रणवीर सिंह के साथ 'सिम्बा' में दिखाई दी, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल साबित हुई।

सारा अगली फिल्मों, कहानियों का चुनाव बेहद सावधानी से कर रही हैं : दमदार किरदार के साथ आना चाहती हैं

किसको क्या मिला.....

- राजीव सातव, अमित चावडा, धानाणी प्रदेश चुनाव समिति में
- अल्पेश ठाकोर को प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया
- जगदीश ठाकोर को बनाया गया प्रचार समिति का सदस्य
- १५ सदस्यों की मीडिया कॉ-ऑर्डिनेशन कमिटी की घोषणा
- नरेश रावल मीडिया कॉ-ऑर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन
- चुनाव प्रबंधन समिति में ९ सदस्यों की घोषणा
- अर्जुन मोढवाडिया चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन
- चुनावी घोषणापत्र समिति में २२ सदस्य शामिल
- मधुसूदन मिस्त्री को बनाया गया चुनावी घोषणापत्र समिति के चेयरमैन
- मनीष दोशी बने चुनावी घोषणापत्र समिति के कन्वीनर

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की का समय में दो घंटे की वृद्धि

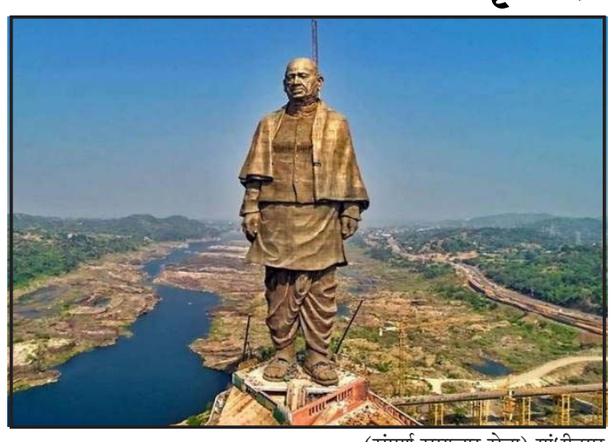

(संपूर्ण समाचार सेवा) गांधीनगर

नर्मदा जिले में गरूडेश्वर तहसील के केवडीया कोलोनी में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के समय में ५ फरवरी, २०१९ को दो घंटे की वृद्धि की गई है। समय में किए गए बदलाव के अनुसार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के लिए समय अब सुबह ८ से शाम के ६ बजे तक रखने का चीफ एडमिनीस्ट्रेटर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवडीया कोलोनी की तरफ से निर्णय लिए जाने का एक अखबारी सूची में बताया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात के समय में यह बदलाव होने से यात्रियों को अब सुबह के ८ बजे से मुलाकात ले सकते है और आगामी गर्मी के सिजन में समय के बदलाव की वजह से यात्रियों की अनुकूलता भी बढ़ेगी। शनिवार-रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में यात्री व्युइंग गेलेरी का लाभ ले सकते है। अब से समय में दो घंटे की वृद्धि होने से हररोज ७००० तक की संख्या में यात्री व्युइंग गेलेरी की मुलाकात का लाभ ले सकते हैं, यह सूची में बताया गया है।

इरफान के लौटने के बाद फिल्म पर काम शुरू

हिंदी मीडियम २ में इरफान खान संग करीना की जोड़ी

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, फिल्म हिंदी मीडियम की शानदार सफलता के तुरंत बाद फिल्म के निर्माता भूषण कुमार और दिनेश विजन ने हिंदी मीडियम २ बनाने की घोषणा की थी। फिल्म के अगले भाग के बनाए जाने को लेकर खुद इरफान खान भी उत्साहित थे, लेकिन इसी बीच इरफान कैंसर जैसी बीमारी के चपेट में आ गए और उन्हें इलाज के लिए न्यू यॉर्क जाना पड़ा। वैसे अब इरफान भारत लौट आए हैं और उनका आगे का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में किया जा रहा है। इरफान के लौटने के बाद एक बार फिर से हिंदी मीडियम २ पर काम शुरू हो गया है। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है और इरफान ने कहानी पढ़ भी ली है। जैसे ही इरफान हरी झंडी देंगे फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। वैसे इन दिनों फिल्म में काम करने वाले कलाकारों का चयन भी किया जा रहा है। खबर है कि इरफान के अपोजिट करीना कपूर खान को कास्ट करने की बात चल रही है। फिल्म की स्क्रिप्ट करीना को सुनाई गई है, जो उन्हें खूब पसंद भी आई है। निर्माता उम्मीद कर रहे हैं कि करीना हिंदी मीडियम २ में काम करने के लिए खुशी-खुशी तैयार हो जाएंगी। अब अगर करीना इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो जाती हैं, तो यह पहली बार होगा जब करीना कपूर खान और इरफान खान एक साथ नजर आएंगे। हिंदी मीडियम की कहानी में एक बच्चे के प्री-स्कूल एडमिशन के दौरान माता-पिता के संघर्ष की कहानी को बड़ी ही बेहतरीन कहानी के साथ दिखाया गया था। फिल्म में इरफान खान के साथ पाकिस्तानी अभिनेत्री सबा कमर थीं। हिंदी मीडियम' में इरफान और सबा की केमेस्ट्री और अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। हिंदी मीडियम २०१७ की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही है।

फिल्म अभिनेता इरफान कैंसर जैसी बीमारी के चपेट में आ गए थे और इलाज के लिए न्यू यॉर्क जाना पड़ा

पीसीबी ने ५००२ बोतल जब्त की : दो गिरफ्तार

सनाथल के पास ट्रक से १६.३९ लाख की शराब जब्त

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात में शराबबंदी का नया सख्त कानून बनाया गया फिर भी बुटलेगर शराब की तस्करी करने में नरम नहीं हुए हैं। गत देर रात को सनाथल हाइवे पर पीसीबी की टीम ने हरियाणा से ट्रक में आ रहा १६.३९ लाख रुपये की शराब के जत्थे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीसीबी की टीम ने ड्राइवर तथा क्लीनर को गिरफ्तार करके पूरी घटना का पर्दाफाश किया है। घटना की वजह से असामाजिक तत्वों में दहशत फैल गई। पीसीबी को जानकारी मिली थी कि, हरियाणा से एक ट्रक में शराब का भारी जत्था अहमदाबाद एसपी. रिंगरोड से सनाथल हाइवे होकर राजकोट जाना है। मिली जानकारी के आधार पर पीसीबी की अलग-अलग टीम बनाकर एसपी. रिंगरोड तथा सनाथल हाइवे पर निगरानी में थे तब हरियाणा पार्सिंग की एक ट्रक रोकी गई थी। पीसीबी की टीम ने ट्रक में भारी मात्रा में शराब जब्त मिला है। शराब को लेकर आते हरियाणा के इमरानखान मेउ तथा मुबारिक मेउ की पीसीबी की टीम ने ट्रक से १६.३९ लाख रुपये की कीमत का ५००२ शराब की बोतलों का जत्था जब्त किया गया। जबकि दस लाख रुपये की ट्रक जब्त करके सरखेज पुलिस स्टेशन में ड्राइवर, क्लीनर तथा ठेकेदार और बुटलेगर के विरूद्ध में शिकायत दर्ज की गई थी। पीसीबी की पूछताछ में ड्राइवर इमरान खान ने बताया कि, यह अंग्रेजी शराब राजकोट के बुटलेगर को पहुंचाने का हरियाणा के ठेकेदार ने बताया था। पुलिस ने प्रोहिबीशन अधिनियम के तहत दोनों शख्सों की पूछताछ करके जांच शुरू कर दी है। पीसीबी के पीएसआई सीएम. चुडासमा ने बताया कि शराब से लदी ट्रक हरियाणा से राजस्थान के उदयपुर में पहुंची थी वहां से यह ट्रक रतनपुर बॉर्डर पार करके शामलाजी से अहमदाबाद पहुंची थी। पीसीबी को जानकारी मिली थी कि शराब से लदी ट्रक रतनपुर बॉर्डर से आयेगी। जिसकी वजह से वह देर रात को निगरानी में थे। सनाथल चौकडी के पास ट्रक आने पर पीसीबी ने इसका पर्दाफाश किया है।

विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी की प्रतिक्रिया

जीवन जीने के लिए योग करना बहुत ही जरूरी है

विधानसभा सचिवालय में कर्मचारियों की स्वास्थ्य जीवन प्रणाली के लिए योग का अध्ययन वर्ग आयोजित किया

(संपूर्ण समाचार सेवा) गांधीनगर, जीवन जीने के लिए योग का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। कार्य में उत्साह बरकरार रहे इसके लिए अन्य तालीम के साथ शांतिमय, स्वस्थ और ताजगीमय जीवन जीने की तालीम भी लेना चाहिए, यह विधानसभा सचिवालय में कर्मचारियों के स्वास्थ्य जीवन प्रणाली के लिए आयोजित किए गए योग अभ्यास वर्ग का शुभारंभ कराते हुए विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी ने बताया। अध्यक्ष ने कहा कि, विधानसभा कर्मचारियों के विकास के लिए पिछले १ वर्ष में यह चौथा कार्यक्रम है। योग में सांस लेने के कई प्रयोग और इसके लाभ पंचतत्व की स्व अनुभव और विजयुलाइजेशन जैसी पद्धति द्वारा जीवन में शांति महसूस होती है जिसकी वजह से अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होती है यह भी त्रिवेदी ने आगे बताया। गणेश वासुदेव मावलंकर संसदीय अभ्यास और तालीम ब्यूरो में आयोजित यह अध्ययन वर्ग में योगगुरु श्रीयुत रक्षाबहन राजे कर्मचारियों को योग और सांस लेने की कई मुद्रा, योग शरीर संचालन में किस तरीके से मददरूप हो सकती है इसके उपाय पेश करके उपस्थित कर्मचारियों को प्रत्यक्ष अध्ययन कराकर योग होते कई लाभों का एहसास हुआ विधानसभा के उप सचिव करोवा ने स्वागत भाषण और शाखा अधिकारी सैयदभाई ने आभार विधि की थी। अध्ययन वर्ग में विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रूचिपूर्वक हिस्सा लेकर इस प्रकार के विकास के आयाम का स्वागत किया गया था।

विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में महत्व की बातें सामने

गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी बजट का प्रमाण १% से कम

सहज, जीआईडीआर और आनंदी संस्था द्वारा आयोजित सेमिनार में गुजरात में टिकाऊ विकास लक्ष्य का रिपोर्ट

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, सहज (सोसाइटी फॉर हेल्थ ऑल्टरनेटिव्ज), जीआईडीआर (गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च) और आनंदी (एरिया नेटवर्किंग एंड डेवलपमेंट इनीशिएटीव) द्वारा आयोजित महत्व के सेमिनार में गुजरात में टिकाऊ विकास लक्ष्यों को (सस्टेनेबल डेवलपमेन्ट गोल्स) की प्रगति की निगरानी रखना। एसडीजी-३ और ५ में से चुनिंदा लक्ष्यों के लिए स्थिति विश्लेषण की रिपोर्ट का मंगलवार को अहमदाबाद में एएमए में विमोचन किया गया। सहज सहित की यह संस्थाओं द्वारा गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए सर्वे और रिसर्च में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई थी। इसके अनुसार, गुजरात सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल के लिए की जाती वित्तीय रकम की आवंटित का प्रमाण लगातार कम हो रहा है। वर्ष २०१५-१६ में वित्तीय आवंटन का इस अनुसार कुल बजट के ५.५९ फीसदी था, जो वर्ष २०१६-१७ में घटकर ५.४ फीसदी हो गया, जबकि २०१७-१८ में सिर्फ ५.०३ फीसदी रहा। विश्व स्वास्थ्य संस्था के अनुसार हरएक देश अपने जीडीपी के कम से कम पांच फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन देना चाहिए लेकिन गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी बजट का प्रमाण कुल बजट के एक फीसदी से भी कम दर्ज किया गया है। जो गंभीर और चिंताजनक कहा जा सकता है यह सहज के डायरेक्टर रेणू खन्ना, आनंदी के डायरेक्टर जीविका शीव और डॉ. तनिष्ठा समन्ता ने बताया। उन्होंने आगे बताया कि, यह रिपोर्ट को छह विभाग में विभाजित किया गया है, जिसमें राज्य की प्रोफाइल, नीति और कार्यक्रम पर्यावरण, मातृत्व स्वास्थ्य, महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा, नुकसानकारक और परंपरागत प्रथा और किसी से पीछे नहीं रहे यह छह विभागों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में महत्व की और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है, जिसमें कई मुद्दे तो ऐसे है जिस पर सरकार सहित के संबंधित शासकों द्वारा लगातार उपेक्षा की गई है या तो नजरअंदाज किया गया है।

देश की प्रथम महिला राजनीतिक पार्टी की अहमदाबाद में घोषणा की गई थी। इस पार्टी की उम्मीदवार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। (संपूर्ण समाचार सेवा)

स्वाइन फ्लू से और ४ की मौत : ५७ नए केस हुए

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात स्वाइन फ्लू के शिकजे में आ गया है। मंगलवार को और ४ लोगों की स्वाइन फ्लू की वजह से मौत हुई थी। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़कर ४७ पर पहुंच गया है। जबकि मंगलवार को २४ घंटे में ही ५७ नए केस सामने आने से संख्या बढ़कर ९५५ पर पहुंच गया। अभी भी ३५५ लोग उपचार के तहत होने की रिपोर्ट मिल रही है जिसमें से कई की हालत गंभीर होने की जानकारी मिली है। जनवरी महीने में ही केस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। फरवरी महीने में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू का आतंक जारी रहा है। मंगलवार को भी और ४ लोगों की मौत होने से मौत का आंकड़ा बढ़कर ४७ पर पहुंच गया है। मंगलवार को जो चार लोगों की मौत हुई थी इसमें से भावनगर, भरूच, जामनगर और कच्छ में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई थी। नए वर्ष में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ने से प्रशासन में खलबली मच गई है। मंगलवार को एक ही दिन में ५७ नए केस सामने आए। सिजनल फ्लू से मौत की घटनाएं बढ़ने से प्रशासन सक्रिय हो गई है। राज्य में स्वाइन फ्लू का आतंक नियंत्रण से बाहर हो गया है। १ जनवरी से लेकर मंगलवार तक ३६ दिनों में मरीजों की संख्या ९५५ से ऊपर पहुंच गई है। सोमवार को नए ६५ केस दर्ज होने के बाद मंगलवार को और ५७ केस सामने आए। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के केस सामने आ रहे है। इसके अलावा सूरत, वडोदरा, जूनागढ़ मनपा में भी केस सामने आये हैं। इस वर्ष राज्य में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या ९५५ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। अनधिकृत रूप से आंकड़ा ९०० से ऊपर है।

भारत के मन की बात अभियान की मंगलवार को विधिवत शुरू की गई। गांधीनगर कमलम से मुख्यमंत्री रुपाणी ने इसकी शुरुआत कराई। (संपूर्ण समाचार सेवा)

२१ मार्च के बाद यातायात पहले जैसा हो सकता है

रनवे मरम्मत : २०-५० प्रतिशत महंगा पड़ेगा मुंबई से आना- जाना

काम ३० मार्च २०१९ तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को होगा : इन दिनो फ्लाईट की आवाजाही नहीं होगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, मुंबई से या मुंबई के लिए उड़ान भरनेवाले लोगों की जेब मार्च के आखिर तक थोड़ी ज्यादा ढीली होनेवाली है। इसकी वजह रनवे रिपेयर है। मिली जानकारी के मुताबिक, रिपेयरिंग का काम ३० मार्च २०१९ तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किया जाएगा। इन दिनों में सुबह ११ से शाम ५ बजे तक फ्लाइट की कोई आवाजाही नहीं होगी। इससे किराया ५० प्रतिशत तक बढ़ सकता है। २१ मार्च के बाद यातायात पहले जैसा हो सकता है। ६ घंटे तक इस क्लोजर की वजह से फ्लाइट कम उड़ेंगी, जिसकी वजह से किराए में अब उछाल आ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। ऐसे में किराए में १५ से २० प्रतिशत की तेजी आ चुकी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर एक दूसरे को काटते दो रनवे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, मरम्मत का काम ठीक उस जगह होना है जहां दोनों जुड़ते हैं। ऐसे में दोनों को ही बंद करना जरूरी हो गया। इस एयरपोर्ट पर प्रति घंटे ४६ फ्लाइट्स आती-जाती हैं। इस तरह एक दिन में २७६ फ्लाइट्स पर असर होगा। मरम्मत के काम से उन दिनों के किराए में भी असर पड़ेगा जिस दिन मरम्मत नहीं होनी होगी। इस बीच मुंबई के दूसरे एयरपोर्ट को जल्द बनाने की मांग भी तेज हो गई है जो साल २००० से की जा रही है।

तेलुगू टीवी ऐक्ट्रेस नागा झांसी ने किया सूइसाइड

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, तेलुगू टीवी ऐक्ट्रेस नागा झांसी ने बुधवार को हैदराबाद स्थित अपने घर पर सूइसाइड कर लिया। नागा (२१) का शव श्रीनगर कॉलोनी में स्थित उनके फ्लैट में पंखे से लटकता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक, ऐक्ट्रेस फ्लैट में अकेली थीं। जब उनके भाई दुर्गा प्रसाद ने दरवाजे को खटखटाया तो कोई अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। जब सभी ने मिलकर दरवाजा तोड़ा तो नागा की पंखे से लटकती बॉडी मिली। अटॉप्सी के लिए ऐक्ट्रेस की बॉडी को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया और पंजगट्टा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया। गौरतलब है कि आंध्रप्रदेश के कृष्णा जिले की रहने वाली झांसी ने मां टीवी पर आने वाले पवित्र बंधन के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम किया था।पिछले कुछ महीनों से अमीरपेट एरिया में ब्यूटी पार्लर चला रही थीं।

रिपोर्ट पर बवाल, बीजेपी का आरोप

तख्तापलट की खबर कांग्रेस के ४ मंत्रियों ने कराई थी प्लांट

कांग्रेस के शासनकाल में न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी किया गया : बीजेपी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, यूपीए-२ सरकार के कार्यकाल के दौरान २०१२ में सैन्य तख्तापलट की उड़ी खबरों को लेकर बीजेपी ने एक अखबार की रिपोर्ट के हवाले से कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सेना के खिलाफ तख्तापलट की गलत खबर छपवाकर उसे बदनाम किया गया। दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनमोहन सरकार के चार मंत्री इस साजिश में शामिल थे। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगने के साथ ही संसदीय कमिटी से इस मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में न केवल भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यूपीए-२ के शासनकाल में भारतीय सेना के खिलाफ साजिश रची गई थी। बता दें कि जनवरी २०१२ में एक न्यूजपेपर में सेना द्वारा कथित तख्तापलट की खबर प्रकाशित हुई थी। इस खबर के बाद देशभर में काफी बवाल मचा था। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भारतीय सेना के खिलाफ खबरें प्लांट करवाई थीं। मनमोहन सरकार के चार मंत्रियों ने देश की आर्मी के खिलाफ गलत खबरें छपवाने की साजिश रची और तख्तापलट की झूठी खबर न्यूजपेपर में छपवाकर सेना का अपमान किया गया। यह देश से गद्दारी थी। बता दें कि द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, सेना की कथित तख्तापलट की खबरों पर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने आईबी के अधिकारियों को बुलाकर इस खबर के बारे में जानकारी मांगी थी। आईबी के अधिकारियों ने तत्कालीन पीएम को बताया कि ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस मामले में शामिल रहे एक अधिकारी ने संडे गार्डियन को बताया कि आईबी ने साफ किया कि तख्तापलट की कोई कोशिश नहीं हो रही है। कहीं भी कोई आर्मी चीफ बिना टॉप अधिकारियों के समर्थन के बिना तख्तापलट की नहीं सोच सकता है।

सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला

सबरीमाला में प्रवेश की रिव्यू पीटिशन पर फैसला सुरक्षित

सुनवाई के दौरान सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं बिंदु और कनकदुर्गा ने भी अपना पक्ष रखा

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली सबरीमाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को लेकर दाखिल की गई रिव्यू पीटिशन पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ उस समय आया मंदिर का कामकाज देखने वाले त्रावणकोर देवासम बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं को भगवान अयप्पा के मंदिर में पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस आरएफ. नरीमन, जस्टिस एएम. खानविलकर, जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच सबरीमाला संबंधी फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली ४८ याचिकाओं पर विचार करेगी। सुनवाई के दौरान मंदिर में प्रवेश करने वाली दो महिलाओं बिंदु और कनकदुर्गा ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मंदिर में प्रवेश के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट में आज उन ४८ याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति वाले उसके २८ सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली ५ जजों की पीठ ने २८ सितंबर को ४-१ के अपने फैसले में सबरीमाला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करते हुए कहा था कि यह पाबंदी लैंगिक भेदभाव के समान है।

चुनाव समितियों की घोषणा करके खेला मास्टरस्ट्रोक

कांग्रेस पार्टी ने नाराज नेताओं को दिया गया चांस

(संपूर्ण समाचार सेवा) गांधीनगर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अलग-अलग समितियों की घोषणा की है। कांग्रेस ने ४३ सदस्यों की प्रचार समिति की घोषणा की है। प्रदेश चुनाव समिति में २८ सदस्यों को शामिल किया गया है। जिसमें उल्लेखनीय मामला है कि, इसमें अल्पेश ठाकोर को प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोरशोर से तैयारी शुरू कर दी है। इसमें भी विधानसभा में कांग्रेस को अच्छा परिणाम देखने को मिला। अब लोकसभा में भी एडीचोटी का जोर लगाने में पीछे नहीं रहेगी। इसी वजह से कांग्रेस द्वारा अलग-अलग प्रचार समिति की घोषणा की गई है। यह समितियों की घोषणा राजीव सातव द्वारा की गई है। जिसमें अल्पेश ठाकोर को महत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोर्डिनेशन कमिटी के चेयरमैन राजीव सातव है। कैंपेन कमिटी चेयरमैन सिद्धार्थ पटेल और कन्वीनर अल्पेश ठाकोर को बनाया गया है। पब्लिसिटी कमिटी चेयरमैन तुषार चौधरी और कन्वीनर रोहन गुप्ता को बनाया गया है। कांग्रेस ने रैली इस घोषणा में पार्टी के सीनियर नेताओं को मनाने का प्रयास किया गया है। अल्पेश ठाकोर की कांग्रेस के प्रति नाराजगी तो स्पष्ट थी, लेकिन इसके पहले कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। यह सभी कमिटी में शामिल किया गया है। इसके साथ जुनियर नेताओं को स्थान दिया गया है। कांग्रेस ने यह समितियों की घोषणा करके आंतरिक कलह को शांत करने का प्रयास किया गया है। सीनियर नेताओं में अर्जुन मोढवाडिया, मौलिन वैष्णव सहित कई नेताओं को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि, चुनाव काम और प्रचार में अभी तक कांग्रेस पार्टी माइक्रोप्लानिंग में कमी रह जाती थी। अब इस मामले में कभी कमी नहीं रखी जाएगी यह कमिटी की घोषणा पर से स्पष्ट होता है।

मायावती सोशल मीडिया से अब तक थीं दूर

मायावती ने ट्विटर पर बनाया अपना आधिकारिक अकाउंट

मायावती का यह अकाउंट अक्टूबर २०१८ में ही बनाया गया था, मगर जनवरी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं था

(संपूर्ण समाचार सेवा) लखनऊ, सोशल मीडिया से जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां चुनावी माहौल तैयार करती हैं, वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) जैसे बड़े राजनीतिक दल ने आज तक सोशल मीडिया से दूरी बना रखी थी। यहां तक किसी बड़े नेता का भी कोई आधिकारिक अकाउंट नहीं था। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक नई शुरुआत की है और ट्विटर पर अपना आधिकारिक अकाउंट बनाया है। मायावती का यह अकाउंट अक्टूबर २०१८ में ही बनाया गया था, मगर जनवरी तक इस पर कोई ट्वीट नहीं था। २२ जनवरी को उन्होंने पहला ट्वीट किया। मायावती ने लिखा, 'नमस्कार भाइयो-बहनो, पूरे सम्मान के साथ मैं आप सबके समक्ष ट्विटर पर कदम रख रही हूं। यह मेरा पहला ट्वीट है। @sushrimayawati मेरा आधिकारिक अकाउंट है और यहीं से मैं भविष्य में आप सबसे जुड़ूंगी। धन्यवाद। बता दें कि मायावती जैसी बड़ी नेता और बीएसपी जैसे बड़े राजनीतिक दल का सोशल मीडिया पर ना होना, उनके समर्थकों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए हैरानी का विषय था। कई बार बीएसपी के नाम से कुछ फर्जी हैंडल भी चर्चा में आए, लेकिन पार्टी ने हमेशा ही इनका खंडन किया और साफ किया कि इनसे बीएसपी का कुछ लेना-देना नहीं है। बुधवार को मायावती का ट्विटर अकाउंट वेरिफाइड भी हो गया और उस पर ब्लू टिक भी आ गया। बीएसपी ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मायावती के ट्विटर अकाउंट के बारे में जानकारी दी है। अकाउंट वेरिफाई होने के बाद मायावती के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। खबर लिखे जाने तक उनके करीब ७,५०० फॉलोअर्स थे।

न्यूजीलैंड ने सीरीज में १-० की बढत बना ली

टी-२० मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को ८० रन से हराया

न्यूजीलैंड ने २० ओवर में ६ विकेट पर २१९ रन बनाए भारतीय टीम १९.२ ओवर में १३९ रन ही बना सकी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, ओपनर टिम सेफर्ट (८४) की शानदार पारी की बदौलत न्यू जीलैंड ने बुधवार को पहले टी२० में भारत को ८० रन से हरा दिया। वेलिंग्टन में खेले गए इस मैच में न्यू जीलैंड ने २० ओवर में ६ विकेट पर २१९ रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम १९.२ ओवर में १३९ रन ही बना सकी। यह टी२० इंटरनैशनल में भारत की रनों के मामले में ओवरऑल सबसे बड़ी हार है। इस जीत के साथ न्यू जीलैंड ने ३ मैचों की सीरीज में १-० की बढ़त बना ली। ओपनर सेफर्ट ने ४३ गेंदों की अपनी पारी में ७ चौके और ताबड़तोड़ ६ छक्के लगाए और टी२० इंटरनैशनल करियर की पहली फिफ्टी जड़ी। उन्होंने पहले विकेट के लिए कोलिन मुनरो (३४) के साथ ८६ रन जोड़े। मुनरो को क्रुणाल पंड्या ने शिकार बनाया और विजय शंकर ने उन्हें लपका। उन्होंने २० गेंदों पर २ चौके और २ छक्के जड़े। सेफर्ट टीम के दूसरे विकेट के तौर पर १३४ के स्कोर पर आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन ने २२ गेदों पर ३ छक्कों की बदौलत ३४ रन का योगदान दिया। वहीं, रोस टेलर ने १४ गेंदों पर २ छक्कों की मदद से २३ रन बनाए। भारत के लिए हार्दिक पंड्या ने २ विकेट लिए लेकिन ५१ रन लुटाए। सबसे किफायती क्रुणाल रहे जिन्होंने ३७ रन देकर १ विकेट लिया। उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद और युजवेंद्र चहल को १-१ विकेट मिला। टी२० इंटरनैशनल में भारत की रनों के मामले में ओवरऑल सबसे बड़ी हार है। इस जीत के साथ न्यू जीलैंड ने ३ मैचों की सीरीज में १-० की बढ़त बना ली। ओपनर सेफर्ट ने ४३ गेंदों की अपनी पारी में ७ चौके और ताबड़तोड़ ६ छक्के लगाए और टी२० इंटरनैशनल करियर की पहली फिफ्टी जड़ी। उन्होंने पहले विकेट के लिए कोलिन मुनरो (३४) के साथ ८६ रन जोड़े। मुनरो को क्रुणाल पंड्या ने शिकार बनाया और विजय शंकर ने उन्हें लपका। उन्होंने २० गेंदों पर २ चौके और २ छक्के जड़े। मेहमान टीम के लिए सबसे ज्यादा रन महेंद्र सिंह धोनी (३९) ने बनाए। उन्होंने ३१ गेंदों की अपनी पारी में ५ चौके और १ छक्का जड़ा। भारतीय टीम को पहला झटका रोहित शर्मा (१) के रूप में पारी के तीसरे ओवर में लगा। इसके बाद धवन (२९) टीम के ५१ के स्कोर पर आउट हुए। उन्होंने १८ गेंदों पर २ चौके और ३ छक्के लगाए। ऋषभ पंत (४) को सैंटनर ने पारी के ९वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिकार बनाया। विजय शंकर (२७) को इसी ओवर की चौथी गेंद पर कोलिन डि ग्रैंडहोम ने लपका। शंकर ने १८ गेंदों की अपनी पारी में २ चौके और २ छक्के लगाए। दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं कर सके और उन्हें ५ के निजी स्कोर पर सोढ़ी ने साउदी के हाथों कैच कराकर पविलियन भेज दिया। हार्दिक पंड्या (४) भी सोढ़ी का शिकार बने और उन्हें मिशेल ने लपका।

आठ फरवरी को सजा सुनाएगा कोर्ट

मुजफ्फरनगर दंगा : कवाल हत्याकांड के सभी दोषी करार

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के कवाल में दो ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या मामले में कोर्ट ने सभी ८ आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिले के एडीजे-७ कोर्ट के जज हिमांशु भटनागर ने मामले की सुनवाई में आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को सजा का ऐलान करने के लिए ८ फरवरी की तारीख तय किया है। गौरतलब है कि ८ आरोपियों में से एक शाहनवाज की पहले ही मौत हो चुकी है। ऐसे में शाहनवाज के अलावा बाकी बचे ७ आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तकरीबन साढ़े ५ साल पहले २७ अगस्त २०१३ को कवाल कांड के बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे भड़क उठे थे। इसमें ६० से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। मामले में शासकीय वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि साल २०१३ में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद विवाद हो गया था। इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम ,मुजम्मिल ,फुरकान ,नदीम ,जहाँगीर ,अफजाल और ईकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल ने जांच के बाद शाहनवाज हत्याकांड में एफआर लगा दी थी। गौरतलब है कि हाल ही में यूपी सरकार ने साल २०१३ में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के ३८ आपराधिक मामलों को वापस लेने की सिफारिश की थी। इन मुकदमों को वापस लेने की संस्तुति रिपोर्ट २९ जनवरी को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजी गई थी। ऐसे में शाहनवाज के अलावा बाकी बचे ७ आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तकरीबन साढ़े ५ साल पहले २७ अगस्त २०१३ को कवाल कांड के बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे भड़क उठे थे। इसमें ६० से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे। मामले में शासकीय वकील आशीष कुमार त्यागी ने बताया कि साल २०१३ में सचिन और गौरव नाम के दो युवकों और आरोपियो में मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद विवाद हो गया था। इसमें दोनों युवकों की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा आरोपी पक्ष के शाहनवाज की भी इस दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद से मुजफ्फरनगर और शामली में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा था। मृतक गौरव के पिता ने जानसठ कोतवाली में कवाल के मुजस्सिम ,मुजम्मिल ,फुरकान ,नदीम ,जहाँगीर ,अफजाल और ईकबाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं मृतक शाहनवाज के पिता ने भी सचिन और गौरव के अलावा उनके परिवार के पांच सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं यूपी सरकार ने पिछले १० जनवरी को इन मुकदमों को वापस लेने की स्वीकृति दी थी।

मुजफ्फरनगर के कवाल में दो ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या मामले में ८ आरोपियों को दोषी करार

वड्रा के सहयोगी की गिरफ्तारी पर रोक १६ फरवरी तक बढ़ी

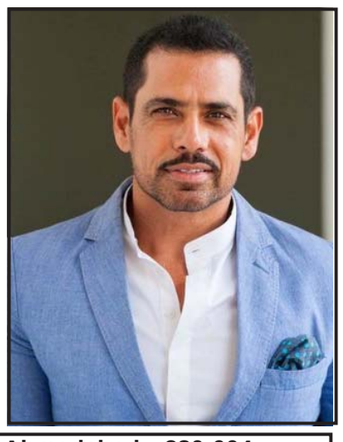

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन के एक मामले में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा की अवधि बुधवार को १६ फरवरी तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार से आग्रह किया कि वड्रा के मामले की अगली सुनवाई १६ फरवरी को तय हुई है इसलिए इस मामले को भी उसी तारीख पर सूचीबद्ध किया जाए।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH